दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

बालाकोट : मोदी का सपना

पिछले रविवार को चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया। सरकार के पक्ष में आयोग ने अपना आखिरी काम भी कर डाला। चुनाव की घोषणा से लोगों ने राहत की सांस ली है- अब और शिलान्यास नहीं होंगे, और अध्यादेश नहीं आएंगे और बिना सोचे-समझे तथा पैसे की कमी से जूझने वाली योजनाओं को 'शुरू' किया जा सकेगा। एक गिनती के अनुसार, तेरह फरवरी को संसद सत्र खत्म होने के बाद से प्रधानमंत्री अब तक एक सौ पचपन योजनाओं का 'उद्घाटन' या 'शिलान्यास' कर चुके हैं।

इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। अमदाबाद मेट्रो का काम 14 मार्च, 2015 को शुरू हो गया था। इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। गुजरात सरकार की इससे बहुत ही खिल्ली उड़ी। यह तय किया गया था कि एक हिस्सा 'पूरा' कर 'सेवा' शुरू कर दी जाएगी। इसलिए जल्दबाजी में साढ़े छह किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पूरी कर दी गई। चार मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ इस सेवा का उद्घाटन किया।

कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। यह लाइन साढ़े छह किलोमीटर लंबी है लेकिन इस पर स्टेशन दो ही हैं, बाकी का निर्माण चल रहा है। इस तरह जो मेट्रो चल रही है वह सिर्फ मौज के लिए है जिसमें कोई टिकट नहीं, कोई किराया नहीं, बस मुफ्त की सवारी!

हां या ना कहिए

अब गंभीर मसलों पर गौर करें। नई सरकार चुनने के लिए करीब नब्बे करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसमें मुख्य मुद्दा मोदी सरकार का कामकाज होगा। कुछ प्रासंगिक सवाल ये हैं-

1- क्या आपको लगता है कि आप एक स्वतंत्र देश के स्वंतत्र नागरिक हैं और अपने धर्म या जाति या भाषा की वजह से भीड़ द्वारा मार दिए जाने, कपड़े उतार कर घुमाए जाने या पीटे जाने या बहिष्कार या भेदभाव का डर नहीं है? यदि आप महिला हैं तो उत्पीड़न या छेड़छाड़ से बेखौफ हैं?

2- क्या आपको भरोसा है कि आपकी बातचीत या संदेशों की सरकार द्वारा जासूसी नहीं की जाएगी?

3- क्या आप मानते हैं कि पिछले पांच सालों में वाकई बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं? यदि आप अभिभावक हैं तो क्या आपको इस बात का भरोसा है कि आपके बेटे या बेटी को जल्द ही नौकरी मिल जाएगी? (सीएमआइई के अनुसार फरवरी 2019 तक नौकरी तलाश रहे नौजवानों की संख्या तीन करोड़ बारह लाख थी।)

4- यदि आप एक किसान हैं तो क्या आपको लगता है कि पिछले पांच सालों में हालात काफी कुछ सुधरे हैं? क्या आपकी आमद बढ़ी है? क्या एक किसान होने की खुशी है आप में और क्या आप अपने बेटे/ बेटी को किसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे?

5- क्या आप मानते हैं कि नोटबंदी एक अच्छा विचार था? नोटबंदी से आपको कोई फायदा हुआ? क्या आपको लगता है कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा हुआ?

6- क्या आप मानते हैं कि कई कर दरों और महीने में तीन रिटर्न वाले जीएसटी से लघु, छोटे और मझौले उद्योगों को कोई फायदा हुआ है? क्या छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी कानूनों के अनुरूप चलना आसान होगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, उससे कारोबारी खुश हैं?

7- क्या मोदी सरकार ने हर व्यक्ति के खाते में पंद्रह लाख रुपए आने, हर साल दो करोड़ रोजगार सृजित करने, विदेशों से कालाधन वापस लाने, अमेरिकी डॉलर को चालीस रुपए तक ले आने, आतंकवाद का खात्मा खासतौर से जम्मू-कश्मीर में और अच्छे दिन लाने जैसे अपने मुख्य चुनावी वादे पूरे किए?

8- क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की बाहुबल, सैन्य और बहुमत पर चलने की नीति जम्मू-कश्मीर में हिंसा को खत्म कर पाएगी और राज्य में खासतौर से घाटी में शांति स्थापित कर पाएगी?

मोदी जी और मित्र

9- क्या आप यह भरोसा कर सकते हैं कि बिना सरकार की जानकारी के विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भारत से भाग गए होंगे?

10- क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार द्वारा किया गया रफाल सौदा दूध का धुला है और हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कीमत पर एक निजी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाया गया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रफाल सौदे पर कीमतों, विमानों की संख्या घटाने, गारंटी संबंधी भारी-भरकम छूट देने, विमानों की आपूर्ति में लगने वाला समय, ऑफसेट पार्टनर का चुनाव आदि को लेकर जांच होनी चाहिए?

11- क्या आप मानते हैं कि प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग आदि स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गई हैं? क्या सीबीआइ के भीतर अधिकारियों की जंग से इस एजेंसी की साख को गहरा धक्का नहीं लगा है?

12- क्या सभी छह हवाईअड्डों (अमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम) के निजीकरण का अनुबंध गुजरात के एक औद्योगिक घराने को दे देना सही था? क्या ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य फैसला था?

उन्माद या बुद्धिमानी

ये ऐसे सवाल हैं जो उन असल मुद्दों की ओर ध्यान खींचते हैं जिनका सामना आज देश कर रहा है। एक नागरिक के रूप में अगर आपका इन मुद्दों को लेकर कोई सरोकार है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सवालों का जवाब दें। आप हां कह सकते हैं या ना कह सकते हैं, लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी सरकार की आखिरी बची-खुची उम्मीद यह होगी कि आप इन सवालों की अनेदखी कर देंगे या किसी भी कीमत पर ये बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पैदा हुए राष्ट्रवाद के जोश में हवा हो जाएंगे।

भारतीय वायुसेना देश की है और इस पर हमें गर्व है। पुलवामा का हमला सरकार की नाकामी का नतीजा था, बालाकोट की कार्रवाई भारतीय वायुसेना की सफलता थी और अगले दिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सरकार की नाकामी थी।

ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं, पुलवामा-बालाकोट उनका जवाब नहीं है। यह डर को खत्म नहीं कर देगा, न ही रोजगार पैदा करेगा या किसानों के गुस्से को शांत करेगा, न ही लघु, छोटे और मझोले उद्योगों में फिर से जान फूंक पाएगा या माल्या, नीरव मोदी और चोकसी को वापस ले आएगा, न ही इससे जांच एजेंसियों की साख फिर से लौटने वाली और न ही इससे कश्मीर घाटी में शांति बहाल हो पाएगी।

नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर केंद्रित हैं और मतदाताओं के बीच एक तरह का उन्माद पैदा करने का इरादा रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि बालाकोट उन्हें जितवा देगा। मेरा मानना है कि भारत के लोग समझदार हैं।

शांति प्रयास और महिलाएं

राजू पांडेय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव सभी संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा करता है कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति और सुरक्षा अभियानों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित और इन गतिविधियों में लैंगिक पहलू का ध्यान रखेंगे। अनेक बार यह सुझाव दिया गया है कि शांति सेनाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए समयबद्ध ठोस लक्ष्य रखे जाएं तथा शांति सेनाओं को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में स्त्री अधिकारों के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जाए। यह भी सुझाव दिया जाता रहा है कि शांति सैनिकों द्वारा महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों की जिम्मेदारी तय और दोषियों को दंडित करने को प्राथमिकता दी जाए। पर इन सुझावों के क्रियान्वयन में पुरुषवादी दृष्टिकोण बाधा बन रहा है।

महिलाएं युद्ध अत्याचारों की सर्वाधिक शिकार होती हैं। युद्ध प्रभावित देशों में लाखों महिलाएं यौन हिंसा और बलात्कार का शिकार होती हैं। मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं न मिलने के कारण इनकी मृत्यु तक हो जाती है। रेड क्रॉस की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था या शिशु जन्म के दौरान असमय मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं में सर्वाधिक संख्या उन दस देशों की महिलाओं की होती है, जहां युद्ध जारी है या हाल ही में समाप्त हुआ है। इन देशों में अफगानिस्तान, कांगो, सोमालिया आदि प्रमुख हैं। आदिकाल से ही पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था में महिलाओं को एक निर्जीव वस्तु की भांति समझा जाता रहा है। युद्ध विजेता अपने सैनिकों के मनोरंजन हेतु या फिर उन्हें पुरस्कृत करने के लिए स्त्री शरीर का पाशविक उपभोग करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। समय बदला है, लेकिन शायद पुरुष की मानसिकता नहीं बदली है। युद्ध के दौरान यौन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को आज भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जब इराक की यजीदी कार्यकर्ता और स्वयं बलात्कार का शिकार रही नादिया मुराद और कांगो के डॉक्टर डेनिस मुकवेगे को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया तब इस अवसर पर उनका भाषण युद्ध क्षेत्र में फंसी महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उदासीनता पर ही केंद्रित था। उन्होंने कहा, 'अपने जीवन के अहम दौर से गुजर रही किशोरियों को बेचा गया, खरीदा गया, बंधक बना कर रखा गया और रोजाना उनके साथ बलात्कार किया गया। यह अकल्पनीय है कि इन सबके बावजूद 195 देशों के नेताओं का जमीर नहीं जागा कि वे इन्हें मुक्त कराने के लिए कार्य करें।' मुराद ने कहा, 'अगर ये लड़कियां कोई व्यापारिक समझौता होती, तेल वाली भूमि होती या विध्वंसक हथियारों से भरा हुआ जहाज होतीं तो निश्चित रूप से इन्हें मुक्त कराने का हर प्रयास कर लिया गया होता।'

पर महिलाओं की युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भूमिका को सर्वाधिक पीड़ित एवं प्रभावित समुदाय की दयनीय स्थिति तक सीमित कर देना उनकी रचनात्मकता, सृजनशीलता और सकारात्मकता की अनदेखी करना है। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति की उपनिदेशक- संचालन, मैरी वेरंटज के अनुसार महिलाएं परिवर्तन की प्रतिनिधि हैं। वे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की स्थापना की मुख्य कारक हैं। वे युद्धकाल में न केवल अपने परिवारों को, बल्कि युद्ध प्रभावित समुदायों को भी एक सूत्र में बांधे रखती हैं। युद्ध महिलाओं की असीमित क्षमताओं को उजागर करने का जरिया भी बनता है। युद्ध में परिवार प्रमुख की मृत्यु के बाद महिलाएं घर की चहारदीवारी से बाहर निकल कर आजीविका अर्जन की जद्दोजहद में लगी नजर आती हैं। हम उन्हें खेतों और कारखानों में कठोर श्रम कर अपने परिवार के भरण-पोषण और शिक्षा आदि की जिम्मेदारी निभाते देखते हैं।

सेनाओं में कार्यरत महिलाओं के प्रदर्शन का आकलन यह बताता है कि महिला शांति सैनिक स्थानीय लोगों से जल्दी घुल-मिल जाती हैं। स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय समाज के इन महिलाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को बदलने में महिला सैनिकों की भूमिका प्रशंसनीय रही है। इसके बावजूद अब भी विश्व के पंद्रह से अधिक देशों में कार्यरत शांति सेनाओं और इनके द्वारा संचालित शांति प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंताजनक तथा असंतोषजनक रूप से कम है। शांति सैनिकों के रूप में इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में कार्यरत अमेरिकी महिला सैनिकों को स्थानीय निवासी पुरुष सैनिकों जैसा विश्वसनीय मानते हैं।

अमेरिकी रक्षामंत्री एश्टन कार्टर ने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2016 से अमेरिकी सेना में महिलाओं को हर प्रकार की युद्धक गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाएगा। पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसास का एक ताजा अध्ययन बताता है कि साथी अमेरिकी सैनिक और उच्च सैन्य अधिकारी आश्चर्यजनक रूप से अब भी महिलाओं को कमतर आंकते हैं। विकसित कहे जाने वाले पाश्चात्य समाजों में भी सेनाओं में महिलाओं की आक्रामक और युद्धक भूमिका को लेकर संदेह व्याप्त रहा है।

लगभग दो दशक से महिलाएं कनाडा की सेना में हर तरह की भूमिका निभाती रही हैं, और उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में छह हजार रूसी महिलाएं बटालियन ऑफ डेथ का हिस्सा रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आठ लाख महिलाएं सोवियत सशस्त्र सेना का हिस्सा रहीं, फिर भी यह पुरुषवादी सोच बदलने का नाम नहीं लेती, जिसके अनुसार महिलाओं में मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति का अभाव होता है। नाटो देशों में अब भी ब्रिटेन, तुर्की और स्लोवाकिया जैसे देश सेना में महिलाओं को सीमित उत्तरदायित्व देने के पक्षधर रहे हैं।

प्रसंग

> समय बदला है, लेकिन शायद पुरुष की मानसिकता नहीं बदली है। युद्ध के दौरान यौन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं को आज भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारा अतीत उन वीरांगनाओं की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है, जिनके शौर्य के सम्मुख हम सब नतमस्तक हैं। वीरांगनाओं की वीरगाथाओं के गायन में हम सब एक स्वर हैं। पर हमारे आधुनिक समाज का दकियानूसी और पितृसत्तात्मक चेहरा भी जगजाहिर है। कुछ माह पहले सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि महिलाओं को 'कॉम्बैट रोल्स' नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उन पर बच्चों के लालन-पालन का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जवान ग्रामीण इलाकों से आते हैं और एक महिला सैन्य अधिकारी का नेतृत्व स्वीकार करना उनके लिए कठिन होगा। युद्ध के दौरान मातृत्व अवकाश न देने पर विवाद खड़ा हो सकता है। भारतीय समाज अभी शहीद वीरांगनाओं के ताबूत देखने को तैयार नहीं है। पता नहीं, जनरल रावत समाज और सेना में व्याप्त धारणाओं को अभिव्यक्ति दे रहे थे या वह उनका निजी मत था। सेना में महिलाओं की भूमिका के संबंध में इस प्रकार की राय नई नहीं है। ब्रिटिश सेना की वरिष्ठतम महिला अधिकारी रही निक्की मोफ्फाट ने ऐसे विचारों को 'सेक्सिजम ड्रेस्ड-अप ऐज कंसर्न' कहा था।

भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाएं केवल अधिकारी के रूप में कार्य कर सकती हैं। वायु सेना की प्रत्येक शाखा में महिला अफसरों की नियुक्ति होती है और वे युद्धक विमान भी उड़ा सकती हैं। थल सेना और नौसेना में महिलाएं शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए नियुक्त होती हैं और युद्ध के अलावा अन्य भूमिकाओं में देखी जाती हैं। इनकी सेवा अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचाराधीन है।

आज जब कश्मीर में आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव चरम पर है और युद्ध की आशंका से प्रत्येक शांतिकामी चिंतित है तब कश्मीरी महिलाओं के हितों, उनकी समस्याओं और उन पर हो रहे अत्याचारों की भी चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर में अशांति और रक्त संघर्ष का लंबा दौर चला है। ह्यूमन राइट्स वॉच एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने सुरक्षा बलों और आतंकवादियों द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों का आकलन किया है। कश्मीर समस्या के समाधान के हर प्रयत्न में जब तक स्त्रियों की भागीदारी नहीं होगी, चाहे वे सैन्य प्रयास हों या सामाजिक राजनीतिक प्रयास, तब तक शायद हिंसा का यह कुचक्र जारी रहेगा।

सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत

एक फौजी अफसर की बेटी होने के नाते मैंने अपना सारा बचपन और आधी जवानी गुजारी है छावनियों में। कभी छावनियां बनी थीं ऐसी जगहों पर, जहां शहर नहीं थे। कुछ बेहाल-सी बस्तियां हुआ करती थीं आला अफसरों के लिए, जहां बिजली अपनी मर्जी से आती-जाती थी। पानी इतना गंदा हुआ करता था कि उबाल कर भी कीटाणु मुक्त नहीं होता था। हमारी बस्तियों से भी बेहाल बस्तियां जवानों की हुआ करती थीं। जवानों के लिए मनोरंजन के तौर पर खुले मैदानों में हफ्ते में एक शाम हिंदी फिल्में दिखाई जाती थीं हवा में झूलते परदों पर। सिनेमाघर लेकिन दूर तक कोई दूसरा नहीं था, सो हम भी देखने जाया करते थे।

अफसरों के लिए क्लब होते थे, बिलकुल वैसे जो अंग्रेजी राज से चले आ रहे थे। एक बड़े से पुराने किस्म के बंगले में बने हुए होते थे खाने-पीने के लिए डाइनिंग रूम और बार। और मनोरंजन के लिए बिलियर्ड रूम और महफिलों के लिए बड़े सारे बॉलरूम जहां बच्चों की बर्थडे पार्टियां भी होती थीं। इन क्लबों में शाम को फौजी अफसर जाया करते थे अपने बीवी-बच्चों को लेकर। इन्हीं क्लबों में मैंने पहली बार रक्षा मंत्रालय का नाम सुना होगा, जब मैं कोई पंद्रह-सोलह साल की थी। उस छोटी उम्र में भी मेरे अंदर एक पत्रकार की जिज्ञासा थी और बड़ों की बातों को चुपके से सुनने की आदत।

सो, अच्छी तरह याद है मुझे कि मेरे पिता और उनके दोस्तों में किस तरह गाली देकर बातें होती थीं रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारियों की और दिल्ली में बैठे राजनेताओं की। गालियां इसलिए दी जाती थीं, क्योंकि फौजी अफसरों को शिकायत थी कि 'इन कमबख्त दिल्ली वालों' को जरा भी संवेदना नहीं है उनके लिए, जो अपनी जान पर खेल कर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। याद है मुझे कि शिकायतें हुआ करती थीं पुरानी बंदूकों की, बेकार असलहे की और जवानों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव की। जब 1962 में चीन ने हमको युद्ध में हराया, तो बहुत बातें सुनने को मिलीं कि किस तरह हमने अपने जवानों को ढंग के बूट तक नहीं दिए थे युद्ध में भेजने से पहले। बहुत गुस्से से कहा करते थे कि नेहरुजी के रक्षामंत्री कृष्णा मेनन ने असलहा के कारखानों में कॉफी मशीनों का उत्पादन शुरू करवाया था।

तबसे लेकर आज तक आधी शताब्दी बीत गई है, लेकिन हाल वही है। कोई दो हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टुडे कॉनक्लेव में जब कहा था कि अगर वायु सेना के पास रफाल विमान होते, तो पाकिस्तान में जिहादी केंद्रों पर हमला ज्यादा आसानी से हो सकता और हमारे पायलट भी ज्यादा सुरक्षित होते। नरेंद्र मोदी के आलोचक फौरन लग गए उनकी आलोचना करने में, लेकिन मेरी राय में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। रफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रयास हम कर रहे हैं एक पूरे दशक से और आज भी उनके आने की संभावना नहीं दिख रही है अगले कुछ वर्षों में। इसलिए कि इस सौदे को घोटाले की शक्ल दे चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कहते हैं अपने हर भाषण में कि प्रधानमंत्री ने 'भारत की जनता का तीस हजार करोड़ रुपए चुरा कर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया है।' पिछले हफ्ते यह रकम पैंतालीस हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दी राहुल गांधी ने, लेकिन आज तक उन्होंने सबूत नहीं पेश किए हैं। सिर्फ आरोप लगाए हैं।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> हर रक्षा सौदे को घोटाला बनाते रहेंगे हम तो कैसे आधुनिकीकरण होगा हमारी सेनाओं का? समस्या सिर्फ वायु सेना की नहीं है, उतनी ही बड़ी समस्या थलसेना और नौसेना की भी है। चीन तो हमसे कोई पच्चीस साल आगे निकल चुका है रक्षा मामलों में, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि हमसे आगे पाकिस्तान भी निकल चुका है कई स्तरों पर।

सबूत हैं उनके पास, तो पेश करना जरूरी हो गया है। बोफर्स सौदे में सबूत की बुनियाद पर आरोप लगे थे। सबूत था कि बोफर्स की रिश्वत का कुछ पैसा ढूंढ़ निकाला था मेरी दोस्त चित्रा सुब्रमण्यम ने उन स्विस बैंक खातों में, जो ओत्तावियो और मारिया क्वात्रोकी के नाम पर थे। क्वात्रोकी खाद बेचने का काम करते थे, सो उनको अगर बोफर्स ने रिश्वत का पैसा दिया था तो सिर्फ इसलिए कि उनकी पहुंच भारत के प्रधानमंत्री के परिवार तक थी, सो बोफर्स कंपनी के काम आए होंगे।

क्या ऐसा कोई सबूत रफाल सौदे में है उनके पास, जो इस सौदे को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं? अनिल अंबानी को अगर नरेंद्र मोदी ने सौदे का आधा पैसा दिलवाया है, तो इसका सबूत पेश करना लाजमी है। अभी तक जो दस्तावेज सामने आए हैं वे सिर्फ यह साबित करते हैं कि इस सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप हो रहा था। सवाल यह है कि इतने बड़े सौदे में क्या प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं होना चाहिए? हस्तक्षेप अगर सिर्फ इसलिए था कि मोदी अनिल अंबानी को सौदे से पैसा चुरा कर देना चाहते थे, तो इसका सबूत पेश करो, वरना वायु सेना को मेहरबानी करके यह विमान जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम करो। ऐसा करना देश के हित में है।

हर रक्षा सौदे को घोटाला बनाते रहेंगे हम तो कैसे आधुनिकीकरण होगा हमारी सेनाओं का? समस्या सिर्फ वायु सेना की नहीं है, उतनी ही बड़ी समस्या थलसेना और नौसेना की भी है। चीन तो हमसे कोई पच्चीस साल आगे निकल चुका है रक्षा मामलों में, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि हमसे आगे पाकिस्तान भी निकल चुका है कई स्तरों पर।

चुनावों के बाद जो भी बनता है भारत का अगला प्रधानमंत्री, उसको रक्षा मंत्रालय पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि ऐसा न होता रहे कि पाकिस्तान जैसा घटिया, जिहादी देश भी हमारे घर के अंदर आकर हमको मारता रहे। मेरा एक दोस्त है, जो रक्षा मामलों में खासी रुचि रखता है, क्योंकि वह खुद सेना में होता था। उसका कहना है कि भारत की सीमाएं तभी सुरक्षित होंगी जब हम अपने रक्षा बजट को दोगुना बढ़ाएंगे, लेकिन रक्षा सौदों में झूठे घोटाले ढूंढ़ना भी बंद करना होगा।

वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहू

हर शाम हिंदी का लगभग हर चैनल एक 'जनता' बनाता है और उसके मुंह में माइक ठूंस कर कहलवाता है कि कौन बनेगा अगला पीएम? किसकी बनेगी अगली सरकार?

कहीं किसी की 'चौपाल' लगी होती है, तो कोई कहीं 'दंगल' करा रहा होता है, कहीं कोई 'जनता' का 'मूड' बता रहा होता है।

'जनता' के नाम पर जुटाए गए 'सलेक्ट लोग' अपने-अपने पक्ष को जिताने के लिए जैसा हल्ला मचाते हैं, वही सीधा प्रसारित होता है और संदेश यही जाता है कि आप कुछ भी कहें सरकार तो यही रहने वाली है! बालाकोट कार्रवाई ने लोगों को अतिरिक्त जोशीला बना दिया है। हिंदी चैनलों की मानें तो भाजपा जीत चुकी है।

एक चैनल ने मूड भांप कर राजग सरकार की 'पॉपुलरिटी की रेटिंग' भी दे डाली, जिसमें 'जनता' के सबसे अधिक 'चहेते' (प्रेफर्ड) पीएम यही नजर आए। बालाकोट के बाद उनकी लोकप्रियता में चार से पांच फीसद इजाफा हुआ बताया गया, जबकि राहुल की लोकप्रियता में एक फीसद की गिरावट आई बताई गई।

इसके बरक्स एक हिंदी चैनल ने सीटों के हिसाब से सर्वे दिया और बताया कि सब कुछ के बावजूद भाजपा को 264 सीटें ही मिल सकती हैं। यूपी में सपा-बसपा 47 सीट ले सकती हैं।... ऐसी ही बातें इस चैनल ने अपने पिछले सर्वे में कही थीं! इसमें नया क्या था?

इसी बीच राहुल ने एक भाषण में तंज कसते हुए कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को मसूद 'जी' क्या कह दिया कि कहर बरपा हो गया!

पहले से ही देशभक्त हुए कई एंकरों को अपने देशप्रेम को प्रदर्शित करने का अवसर मिल गया। इसके बाद राहुल की जो चौतरफा ठुकाई हुई, वह याद रहेगी। सब एंकर एक स्वर में कोसने लगे कि दिग्विजय ने ओसामा 'जी' कहा था, राहुल ने मसूद 'जी' कहा। कैसी समानता है!

दूसरे एंकर ने ताना कसा : 'राहुल लव्स टेररिस्ट्स'! राहुल आतंकवादियों को प्यार करते हैं! एक और एंकर दहाड़ा : भारत के दुश्मन आतंकवाद के सरगना मसूद के नाम के आगे 'जी' लगा कर उसे इतना सम्मान क्यों दिया?

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने समझाया कि राहुल का पूरा वक्तव्य देखें। वे तो व्यंग्य में कह रहे थे!

सर जी! वह व्यंग्य भी क्या कि जिसको अलग से 'अर्थाना' पड़े? और यह भी व्यंग्य कम 'काकु कथन' अधिक था। लेकिन दिन-रात देश को बचाने में व्यस्त एंकरों को इससे क्या? वे तो भाषा के मोटे-मोटे अर्थ ही समझ सकते हैं। 'जी' के 'काकु' को जिस तरह भाजपा के प्रवक्ताओं ने 'अभिधा' में लिया, उसी तरह एंकरों ने लिया! 'काकु' की बारीकियां समझें कि देश के दुश्मन को कूटें!

एक एंकर ने राहुल पर तरस खाया कि राहुल के पास न 'विजन' (दृष्टि) है न 'कैपेसिटी' (क्षमता) है!

दूसरा एंकर, जो हमेशा गुस्से में गरजता रहता है, एक बार फिर गरजा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग मुझसे तथा देश से माफी मांगें!

'देश से माफी मांगें' ये तो समझ आता है, लेकिन एंकर जी! तू क्या देश से भी बड़ा है?

कोढ़ में खाज इसी को कहते हैं कि जब राहुल हर चैनल पर मार खा रहे थे तभी टॉम वडक्कन कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए!

एक अंग्रेजी चैनल पर आकर टॉम वडक्कन ने बताया कि पुलवामा असली कारण बना। कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए। इससे मैं सहमत न था। मेरे लिए कांग्रेस से देश महत्त्वपूर्ण है। दफ्तर में बीस लोग होते हैं। कोई नीति के बारे में नहीं सोचता। जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तो वफादार बाहर हो जाते हैं।... भाजपा की विचारधारा मुझे पंसद आई।...

बीस साल तक एक विचार के प्रवक्ता और फिर एक दिन जिसकी जिंदगी भर आलोचना करते रहे, उसी की चरण वंदना! राजनीतिक शीर्षासन इसी को कहते हैं।

लेकिन दलबदल का मामला भी एकतरफा न रहा। इधर टाम वडक्कन भाजपा के अंगवस्त्र से सज्जित दिखे, तो लगभग उसी समय में एक चैनल पर उत्तराखंड के बड़े भाजपा नेता खंडूरी के सुपुत्र कांग्रेस में जाते दिखे! हिसाब बराबर!

ये ऐसे ही चमत्कारी दिन हैं। कल तक पार्टी का दुश्मन रहा बंदा पार्टी में आते ही देवता बन जाता है। विचारधारा गई तेल लेने!

इसके आगे ठुकने की बारी चीन की होनी थी, जिसने मसूद को 'बैन' होने से बचाया। लेकिन चीन का भाग्य देखिए कि मसूद अजहर को यूएन द्वारा प्रतिबंधित करने में चौथी बार अड़ंगा डालने पर भी चीन को न किसी प्रवक्ता ने यथेष्ट कोसा, न चीन की भर्त्सना की, बल्कि भाजपा द्वारा चीन के अड़ंगे के लिए भी नेहरू को ही अपराधी ठहरा दिया गया।

चीन के सर्वेसर्वा जिन पिंग के साथ पीएम की झूला-कूटनीति पर राहुल के कटाक्ष का जवाब देते हुए भाजपा के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रत्यारोप लगाया कि यह नेहरू ही थे, जिनने चीन को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने दिया! इस तर्क से अजहर को बैन करने में चीन के अड़ंगे के लिए नेहरू ही जिम्मेदार हुए!

मसूद दुश्मन, तो उसे पालने वाला पाकिस्तान दुश्मन! एकदम सही बात। लेकिन उसे बार-बार बचाने वाला चीन दुश्मन क्यों नहीं? उसकी कुटाई क्यों नहीं की गई? हमारे परमवीर एंकर चीन को लेकर क्यों चुप लगा गए?

सच कहा है : वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहू!

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> मसूद दुश्मन, तो उसे पालने वाला पाकिस्तान दुश्मन! एकदम सही बात। लेकिन उसे बार-बार बचाने वाला चीन दुश्मन क्यों नहीं? उसकी कुटाई क्यों नहीं की गई? हमारे परमवीर एंकर चीन को लेकर क्यों चुप लगा गए?

नई दिल्ली